Part XII: Finance, Property, Contracts and Suits

Part XII of the Constitution of India deals with Finance, Property, Contracts, and Suits. It contains provisions regarding the financial powers and responsibilities of the Union and the States, the regulation of property, contracts, and suits, and the jurisdiction of courts with respect to these matters.

Article 265 provides for the obligation of the States to not engage in any trade or business, and lays down the responsibility of the Union to ensure that the States do not do so.

Article 266 provides for the control of the Union over the public finances of the States, and lays down the provisions regarding the consolidation and management of the revenues of the Union and the States.

Article 267 provides for the administration of inter-State trade and commerce, and lays down the provisions regarding the levying of taxes on such trade and commerce by the Union and the States.

Article 298 provides for the regulation of contracts, and lays down the provisions regarding the enforceability of contracts entered into by the Union, the States, and the citizens of India.

Article 299 provides for the jurisdiction of courts with respect to disputes arising out of contracts, and lays down the provisions regarding the power of the Union and the States to sue or be sued.

Article 300 provides for the right of the Union and the States to acquire and hold property, and lays down the provisions regarding the protection of the rights of the Union and the States with respect to their property.

Overall, Part XII of the Constitution of India lays down the provisions regarding the financial powers and responsibilities of the Union and the States, the regulation of property, contracts, and suits, and the jurisdiction of courts with respect to these matters, and aims to ensure the proper functioning of the financial and legal systems in India.

भाग बारहवीं: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट

भारत के संविधान का भाग XII वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है। इसमें संघ और राज्यों की वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों, संपत्ति, अनुबंधों और मुकदमों के विनियमन और इन मामलों के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।

अनुच्छेद 265 किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होने के लिए राज्यों के दायित्व का प्रावधान करता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए संघ की जिम्मेदारी निर्धारित करता है कि राज्य ऐसा नहीं करते हैं।

अनुच्छेद 266 राज्यों के सार्वजनिक वित्त पर संघ के नियंत्रण का प्रावधान करता है, और संघ और राज्यों के राजस्व के समेकन और प्रबंधन के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 267 अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के प्रशासन के लिए प्रदान करता है, और संघ और राज्यों द्वारा ऐसे व्यापार और वाणिज्य पर कर लगाने के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 298 अनुबंधों के विनियमन के लिए प्रदान करता है, और संघ, राज्यों और भारत के नागरिकों द्वारा किए गए अनुबंधों की प्रवर्तनीयता के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 299 अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के लिए प्रदान करता है, और मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने के लिए संघ और राज्यों की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 300 संघ और राज्यों को संपत्ति अर्जित करने और धारण करने का अधिकार प्रदान करता है, और उनकी संपत्ति के संबंध में संघ और राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग XII संघ और राज्यों की वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों, संपत्ति, अनुबंधों और मुकदमों के नियमन और इन मामलों के संबंध में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों को निर्धारित करता है, और इसका उद्देश्य है भारत में वित्तीय और कानूनी प्रणालियों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना।